



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## रुड़की

खण्ड-22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 जुलाई, 2021 ई0 (श्रावण 09, 1943 शक सम्वत्) [संख्या-31

### विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	429-436	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	293-302	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	—	975
स्टोर्स पर्वेज-स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	—	1425

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

28 मई, 2021 ई०

संख्या 921/XXXii/2021/37(02)/2016टी०सी०-तात्कालिक प्रभाव से श्री रंजन मिश्रा, वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी को नियमित चयनोपरान्त मुख्य व्यवस्थाधिकारी वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री रंजन मिश्रा को 02 वर्ष तक विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3- श्री रंजन मिश्रा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

रमेश कुमार सुधांशु,

प्रमुख सचिव।

## पंचायतीराज अनुभाग-2

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

24 जून, 2021 ई०

संख्या 281/XII(2)/2021/90(35)2005-श्री कबूल चन्द, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उत्तरकाशी जिनकी जन्मतिथि अभिलेखानुसार दिनांक 15.07.1961 है, की 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु दिनांक 31.07.2021 को पूर्ण होने के फलस्वरूप नियमानुसार श्री कबूल चन्द दिनांक 31.07.2021 को अपराह्न से जिला पंचायत की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

हरि चन्द्र सेमवाल,

सचिव।

## वित्त अनुभाग-6

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

01 जुलाई, 2021 ई०

संख्या 319/XXVII(6)-एक-1162/2015/2021-उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021-22 हेतु ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-एक (वेतनमान ₹0 15600-39100, ग्रेड पे0 ₹0 7600/-) में कार्यरत अधिकारियों को चयन वेतनमान (₹0 37400-67000 ग्रेड पे ₹0 8700, पुनरीक्षित वेतनमान ₹0 1,23,100-2,15,900 लेवल-13) में पदोन्नति हेतु सम्पन्न हुयी विभागीय चयन समिति की बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित अधिकारियों को चयन वेतनमान (₹0 37400-67000 ग्रेड पे ₹0 8700, पुनरीक्षित वेतनमान ₹0 1,23,100-2,15,900 लेवल-13) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.

नाम

1. श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव
2. श्री विक्रम सिंह जन्तवाल
3. श्री मनीष कुमार उप्रेती
4. श्रीमती रुचिता तिवारी
5. श्री खजान चन्द्र पाण्डेय
6. श्री भूपेन्द्र प्रसाद काण्डपाल
7. मो० गुलफाम अहमद
8. श्रीमती अनीता आर्य
9. श्री नरेन्द्र सिंह
10. श्री वीरेन्द्र कुमार

2- उपर्युक्तानुसार पदोन्नत किये जा रहे अधिकारियों को पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3- वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उक्तवत् पदोन्नत अधिकारी, इस आदेश के क्रम में अपने मूल तैनाती स्थान पर ही, पदोन्नत पद के प्रति कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4- पदोन्नत अधिकारियों का तैनाती आदेश कालान्तर में पृथक से निर्गत किया जायेगा। अग्रिम आदेशों तक उक्त अधिकारी अपना मूल एवं अतिरिक्त कार्यप्रभार का निर्वहन यथावत् करते रहेंगे।

5- पदोन्नत पद के प्रति अपने मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी, पूर्व से ही यदि उच्चतर वेतनमान के पद पर कार्यरत न हों, तो भी अपने मूल तैनाती स्थल पर ही पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं ऐसे अधिकारियों का पदोन्नत पद के प्रति किये गये योगदान के सापेक्ष वेतन आहरण वित्त सेवा संवर्ग के समग्र ढांचे एवं अन्य विभागीय ढांचों में सृजित पदों के विपरीत आहरित किया जायेगा। इस हेतु निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड अपने स्तर से सभी कोषागारों एवं विभागाध्यक्षों से समन्वय बनाते हुये वेतन अग्रहरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे, जो पदधारक राज्य सरकार से इतर स्वायत्तशासी निकाय/विश्वविद्यालय आदि में मूल प्रभार के रूप में तैनात हैं, उनका पदोन्नति के पद का वेतन उक्त इकाईयों से आहरित किया जायेगा।

6- उपर्युक्तानुसार पदोन्नत किये जा रहे अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

सौजन्या,

सचिव।

## सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2

### अधिसूचना

### विविध

08 जुलाई, 2021 ई०

संख्या 926/II(2)/2021-06(15)/2020-राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद टिहरी गढ़वाल के भिलंगना नदी के दोनों किनारों पर गंगी से घनसाली तक 68.00 कि०मी०, गंगा नदी के दांये किनारे पर देवप्रयाग संगम से ढालवाला झ्रन मुनिकी रेती तक 68.00 कि०मी०, मागीरथी के दोनों किनारों पर कोटेश्वर डैम से देवप्रयाग संगम तक 22.50 कि०मी०, अलकनन्दा के दांये किनारे पर श्रीनगर डैम से देवप्रयाग संगम तक 37.00 कि०मी० रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1829/II(2)-2020-06(15)/2020, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 में संलग्न अनुसूची-1 एवं 2 में वर्णित क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात:-

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमत्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियाँ, समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमत्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमत्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमत्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the 'Constitution of India', The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.926/II(2)/2021-06(15)/2020 dated July 08, 2021 for general information.

#### NOTIFICATION

#### Miscellaneous

July 08, 2021

No.926/II(2)/2021-06(15)/2020—In exercise of the powers conferred by sub Section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act. No 07 of 2013) the Governor is pleased to accord sanction of following work execution in these area with declaration flood plain zoning to the mentioned area annexed schedule 1 and 2 of the previous notification no- 1829/II(2)-2021-06(15)/2020, dated 28.09.2020 on both side river Bhilangna Gangi to Ghansali 68.00 km, Right side river Ganga Devprayag sangam to Dhalwala drain Muniki reti 68.00 km, both side river Bhagirathi Koteswar dam to Devprayag sangam 22.50 km, Right side river Alaknanda Srinagar dam to Devprayag sangam 37.00 km of District Tehri Garhwal, namely-

S.No.	Area	Details of Permissible Works
1.	Prohibited Area	Construction/Activities regarding embankment/ flood Management, Mining, Plantation, Agriculture, Bathing Ghats, River Front development, Irrigation, Drinking water scheme, Water sports, Water transportation and Bridge etc.
2.	Restricted Area	Construction/Activities regarding Park, Sports Field, Fisheries, Agriculture etc. and the temporary construction required for religious fairs from time to time shall be permissible after getting N.O.C. from Uttarakhand Peyjal Nigam that there are appropriate management for disposal of sewerage and solid waste created by the said activities in this area. The reconstruction of existing unsafe structure shall be admissible up to limitation of existing land covering 35% floor area ratio 1.5 and up to maximum height 7.50 meter or double storey building with the restriction that the sewerage system is available in the area. In case of admissibility of construction, minimum plinth level of the building from High Flood Level (H.F.L) shall be kept 1.0 M high and the examination/N.O.C. shall be necessary from the Uttarakhand Peyjal Nigam for ensuring that there are appropriate provision of Sewerage treatment.

अधिसूचनाविविध

08 जुलाई, 2021 ई०

संख्या 927/II(2)/2021-06(66)/2016—राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद उत्तरकाशी के भागीरथी नदी के दोनों किनारों पर गंगोत्री से गंगनानी तक 42.00 कि०मी०, गंगनानी से गंगोरी तक 33.85 कि०मी०, बडेथी चुंगी से धरासू पावर हाउस (चिन्यालीसौर तक) 25.00 कि०मी० रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1866/II(2)-2020-06(66)/2016, दिनांक 05.10.2020 में संलग्न अनुसूची-1 एवं 2 में वर्णित क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात:-

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमत्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियाँ, समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमत्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी० अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमत्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमत्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the 'Constitution of India', The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.927/II(2)/2021-06(66)/2016 dated July 08, 2021 for general information.

NOTIFICATIONMiscellaneous

July 08, 2021

No.927/II(2)/2021-06(66)/2016—In exercise of the powers conferred by sub Section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act. No 07 of 2013) the Governor is pleased to accord sanction of following work execution in these area with declaration flood plain zoning to the mentioned area annexed schedule 1 and 2 of the previous notification no- 1866/II(2)-2020-06(66)/2016, dated 05.10.2020 from Gangotri to Gangani reach up to 42.00 Km, Gangani to Gangori reach up to 33.85 Km and Gangori to Badethi Chungi to Dharasu power house (chinyalisaur) 25.00 Km on both side of river Bhagirathi of District Uttarkashi, namely-

S.No.	Area	Details of Permissible Works
1.	Prohibited Area	Construction/Activities regarding embankment/flood Management, Mining, Plantation, Agriculture, Bathing Ghats, River Front development, Irrigation, Drinking water scheme, Water sports, Water transportation and Bridge etc.

2. Restricted Area Construction/Activities regarding Park, Sports Field, Fisheries, Agriculture etc. and the temporary construction required for religious fairs from time to time shall be permissible after getting N.O.C. from Uttarakhand Peyjal Nigam that there are appropriate management for disposal of sewerage and soild waste created by the said activities in this area. The reconstruction of existing unsafe structure shall be admissible up to limitation of existing land covering 35% floor area ratio 1.5 and up to maximum height 7.50 meter or double storey building with the restriction that the sewerage system is available in the area. In case of admissibility of construction, minimum plinth level of the building from High Flood Level (H.F.L) shall be kept 1.0 M high and the examination/N.O.C. shall be required from the Uttarakhand Peyjal Nigam for ensuring that there are appropriate provision of Sewerage treatment.

### अधिसूचना

#### विविध

08 जुलाई, 2021 ई०

संख्या 928/II(2)/2021-06(16)/2020—राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद चमोली में अलकनन्दा नदी के दायां तट पर माणा से तौली लगा रानो 135.00 कि०मी०, अलकनन्दा नदी के बायां तट माणा से सोनला तक 112.00 कि०मी०, अलकनन्दा नदी के बायां तट पर सोनला से कमेड़ा तक 22.00 कि०मी० रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1874/II(2)-2020-06(16)/2020, दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 में संलग्न अनुसूची-1 एवं 2 में वर्णित क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात:-

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियों, समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी० अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

एस०ए०मुरुगेशन,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the 'Constitution of India', The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.928/II(2)/2021-06(16)/2020 dated July 08, 2021 for general information.

**NOTIFICATION**

**Miscellaneous**

**July 08, 2021**

**No.928/II(2)/2021-06(16)/2020**—In exercise of the powers conferred by sub Section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act. No 07 of 2013) the Governor is pleased to accord sanction of following work execution in these area with declaration flood plain zoning to the mentioned area annexed schedule 1 and 2 of the previous notification no- 1874/II(2)-2021-06(16)/2020, dated 07.10.2020 on Right side river Alaknanda Mana to Touli Laga Rano 135.00 Km, Left side river Alaknanda Mana to Sonla 112.00 Km Left side river Alaknanda Sonla to Kameda 22.00 of District Chamoli, namely-

<b>S.No.</b>	<b>Area</b>	<b>Details of Permissible Works</b>
1.	Prohibited Area	Construction/ Activities regarding embankment/flood Management, Mining, Plantation, Agriculture, Bathing Ghats, River Front development, Irrigation, Drinking water scheme, Water sports, Water transportation and Bridge etc.
2.	Restricted Area	Construction/Activities regarding Park, Sports Field, Fisheries, Agriculture etc. and the temporary construction required for religious fairs from time to time shall be permissible after getting N.O.C. from Uttarakhand Peyjal Nigam that there are appropriate management for disposal of sewerage and soild waste created by the said activities in this area. The reconstruction of existing unsafe structure shall be admissible up to limitation of existing land covering 35% floor area ratio 1.5 and up to maximum height 7.50 meter or double storey building with the restriction that the sewerage system is available in the area. In case of admissibility of construction, minimum plinth level of the building from High Flood Level (H.F.L) shall be kept 1.0 M high and the examination/N.O.C. shall be necessary from the Uttarakhand Peyjal Nigam for ensuring that there are appropriate provision of Sewerage treatment.

By Order,

**S.A. MURUGESAN,**

Secretary.

## न्याय विभाग

## कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र

05 जुलाई, 2021 ई0

पत्रांक संख्या 127/XXXVI/न्याय विभाग/2021-प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा संयुक्त सचिव न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन का कार्यभार दिनांक 03.05.2021 से दिनांक 02.07.2021 तक (दिनांक 01 एवं 02 मई, 2021 को प्रीफिक्स तथा 03 एवं 04 जुलाई, 2021 को सफिक्स करते हुए) बाल्य देखभाल अवकाश उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4 के आदेश संख्या 435/XXX(4)/2021-04(2)/2019 टी0सी0, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 से स्वीकृत होने एवं उपभोग करने के पश्चात् आज दिनांक 05.07.2021 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

श्वेता पाण्डेय,

संयुक्त सचिव न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

प्रतिहस्ताक्षरित,

राजेन्द्र सिंह,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

## राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3

## प्रोन्नति/विन्नति

14 जून, 2021 ई0

संख्या 1043/XXXii-3-2021-37(02)/2016-तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित कार्मिकों को नियमित चयनोपरान्त, वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी के पद (वेतनमान-₹ 15600-39100 ग्रेड पे-₹ 5400, मैट्रिक्स लेवल-10) पर पदोन्नत करते हुये, उनकी वर्तमान तैनाती स्थल में ही कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	पदोन्नत पदनाम	वर्तमान/पदोन्नति के फलस्वरूप/ तैनाती स्थल
1	2	3	4
1.	श्री सतीश कुमार/व्यवस्थाधिकारी	वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी	बीजापुर राज्य अतिथिगृह, देहरादून।
2.	श्री मुन्ना प्रसाद/व्यवस्थाधिकारी	वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी	सर्किट हाऊस ऐनैक्सी, देहरादून।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त कार्मिकों को 02 वर्ष तक विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. उक्तानुसार पदोन्नत कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी योगदान आख्या अपने तैनाती स्थल के प्रभारी अधिकारी के समक्ष तत्काल प्रस्तुत कर तदनुसार सूचना राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,

सचिव (प्रभारी)/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 हिन्दी गजट/268-भाग-1-2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 जुलाई, 2021 ई0 (श्रावण 09, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज़ाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, PITHORAGARH

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

April 15, 2021

Letter No. 251/I-03-2018—Certified that the office of the Chief Judicial Magistrate, Pithoragarh was handed over under the orders of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital vide Notification No.88/UHC/Admin.A/2021, dated April 08, 2021, as hereinafter denoted, in the afternoon of April 15, 2021.

SUDHIR TOMAR,

Chief Judicial Magistrate,

Pithoragarh.

Counter-Signed,

Illegible,

I/c District Judge,

Pithoragarh.

CERTIFICATE OF TAKEN OVER CHARGE

April 17, 2021

Letter No. 253/I-01-2021---Certified that the office of the Civil Judge (Junior Division), Didihat, District Pithoragarh was taken over under the orders of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital vide Notification No. 125/UHC/Admin.A/2021, dated April 08, 2021, as hereinafter denoted, in the afternoon of April 16, 2021.

BEENU GULYANI,

Civil Judge (Jr. Div.),

Didihat,

District Pithoragarh.

Counter-Signed,

Illegible,

I/c District Judge,

Pithoragarh.

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार मुक्त प्रमाण-पत्र

17 अप्रैल, 2021 ई०

पत्रांक 254/I-09-2017-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के परिपत्र संख्या-152/UHC/Admin.A/2021, दिनांकित 08 अप्रैल, 2021 के अनुपालन में, मेरे द्वारा आज दिनांक 15-04-2021 को अपराह्न में सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) गंगोलीहाट, जिला-पिथौरागढ़ का पदभार छोड़ा गया।

अनिल कुमार कोरी,

सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक

मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), गंगोलीहाट।

प्रतिहस्ताक्षरित,

ह० (अस्पष्ट)

I/c जनपद न्यायाधीश,

पिथौरागढ़।

## OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE PITHORAGARH

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

April 30, 2021

Endorsement No. 263(8)/I-10-2020---Certified that the office of the District & Sessions Judge, Pithoragarh was handed over on proceeding to medical leave w.e.f. 13-04-2021 to 29-04-2021 in anticipation of sanction of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital as hereinafter denoted, in the forenoon of April 13, 2021.

DR GYANENDRA KUMAR SHARMA,

*District & Sessions Judge,  
Pithoragarh.*

Counter-Signed,

Illegible,

Registrar General,

Hon'ble High Court of Uttarakhand,

Nainital.

CERTIFICATE OF TAKEN OVER CHARGE

April 30, 2021

Endorsement No. 264(7)/I-10-2020---Certified that the office of the District & Sessions Judge, Pithoragarh was taken over after availing medical leave w.e.f. 13-04-2021 to 29-04-2021 in anticipation of sanction of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital as hereinafter denoted, in the forenoon of April 30, 2021.

DR. GYANENDRA KUMAR SHARMA,

*District & Sessions Judge,  
Pithoragarh.*

Counter-Signed,

Illegible,

Registrar General,

Hon'ble High Court of Uttarakhand,

Nainital

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITYHIGH COURT CAMPUS, NAINITALNOTIFICATION

June 19, 2021

No.582/III-A-02/2021/SLSA---Ms Tricha Rawat, Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for a period of 47 days w.e.f. 26.04.2021 to 11.06.2021 alongwith permission of prefix of 25.04.2021 as Sunday holiday and suffix of 12.06.2021 and 13.06.2021 as second Saturday and Sunday holiday respectively.

By Order of Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

R.K. KHULBEY,

Member Secretary

## OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE PITHORAGARH

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGEMay 14, 2021June 23, 2021

**Letter No. 383/I-3-2021**---Certified that the charge of the office of Civil Judge (Junior Division) Gangolihat, District-Pithoragarh is handed over on proceeding to Medical Leave from dated 27-04-2021 to 13-05-2021 in anticipation of sanction of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital as hereinafter denoted, on dated April 27, 2021.

**SACHIN KUMAR,**

*Civil Judge (Junior Division),  
Gangolihat.*

Counter-Signed,

Illegible,

*District Judge,**Pithoragarh.*CERTIFICATE OF TAKEN OVER CHARGEMay 14, 2021June 23, 2021

**Letter No. 384/I-3-2021**---Certified that the charge of the office of Civil Judge (Junior Division) Gangolihat, District-Pithoragarh is taken over after availing Medical Leave from dated 27-04-2021 to 13-05-2021 in anticipation of sanction of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital, as hereinafter denoted, in the forenoon of May 14, 2021.

**SACHIN KUMAR,**

*Civil Judge (Junior Division),  
Gangolihat.*

Counter-Signed,

Illegible,

*District Judge,**Pithoragarh.*

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE  
(C.M.S.D. SECTION) UTTARAKHAND, DEHRADUN

NOTIFICATION NO. 03 (M)July 01, 2021RATE CONTRACT OF MEDICINES

**Letter No.15 P/Store/22/2021/13434**---In exercise of the power delegated in G.O No 712/XXVIII-3-2019-15/2019 dated 27-09-2019 the rate contract of medicine mentioned in Annexure 'B' is made with the firms mentioned in Annexure 'A' for the supply in the state Government in Medical & Health services Department for the period ending on the following terms and conditions:

1. The firms shall made supplies in manufactures original packing as indicated in column-3 of *Annexure B* for name of makes unless otherwise stated. The supplying firms will be required to clearly mention on the label the name of the manufacturer.
2. The firms will have to give a written warranty in accordance with drugs Act 1940 Rule 19 Para3 (8) to the effect that supplies confirm to the approved standard prescribed in the Drugs rule 1940 enforced and as given in this notifications.
3. Indenting Officers may place order direct on these firms as mentioned is attached Annexure A and B.

#### 4. Delivery Schedule

The Purchaser requires that the medicine, surgical items and chemicals under the Rate Contract shall be delivered within three (03) weeks starting from the date of signing of the Purchase order.

5. All the Medicines/surgical items and chemicals to supply, shall not be older than 1/6<sup>th</sup> of interval of manufacturing and expiry date i.e. to say, if any medicine expires after 3 years of its manufacturing date, then at the time of supply the manufacturing date should not be more than 6 months old. Vaccines, biological products and imported medicines/surgical items, the remaining life should be 3/5<sup>th</sup> (60 %). In special circumstances, with approval of Director General, MH&FW, an exemption of 3 months may be accepted with the condition that if any of the item(s) may not be used before the date of expiry, the Bidder shall replace remaining quantity of such items, but remaining life of such items should be more than 50 %, for which Bidder had submitted an affidavit.

#### 6. Packing of medicines/drugs/vaccines

- 6.1 Outside the cartons, all other type of packing's, each vials, ampoules, bottles, medicines & capsule's sterilized safe packing's, the supplier should clearly print "U.K. GOVT. SUPPLY, NOT FOR SALE" with indelible ink.
- 6.2 The Supplier shall provide such packing of the Medicine, surgical items and chemicals as is required to prevent their damage or deterioration during transit to their final destination as indicated in the Contract. The packing shall be sufficient to withstand, without limitation, rough handling during transit and exposure to extreme temperatures, salt and precipitation during transit and open storage. Packing case size and weights shall take into consideration, where appropriate, the remoteness of the Medicine, surgical items and chemicals' final destination and the absence of heavy handling facilities at all points in transit.
- 6.3 The packing, marking and documentation within and outside the packages shall comply strictly with such special requirements as shall be provided for in the Contract including additional requirements, if any, and in any subsequent instructions ordered by the Purchaser.

#### 7. Transportation

Where the Supplier is required under the Contract to transport the Medicine, surgical items and chemicals to a specified place of destination i.e. consignee with in Uttarakhand, transport to such place of destination/consignee in Uttarakhand including insurance, as shall be specified in the Contract, shall be arranged by the Supplier, and the related cost shall be included in the Contract Price.

## 8. Quality of medicines

8.1 The Supplier shall mandatorily submit in house test report at the time of supply of medicine(s), surgical item(s) and chemical(s) for all the batches

8.2 All medicine, surgical items and chemicals found of below standard shall be the responsibility of the Supplier.

8.3 Samples of all the batches of medicine, surgical items and chemicals supplied under Contract, shall be tested at reputed Government approved laboratories/institution.

8.4 Maximum permissible limit of the size of tablets, capsules, injection, syrup, iv fluids etc shall be up to rupees 1.0 lakh quantity-2 batches, above 1.0 lakh and up to 3 lakh quantity-5 batches, above 3.0 lakh and up to 5 lakh quantity-7 batches and above 5.0 lakh, -1 batch per lakh quantity. The cost incurred on above quality testing shall be borne by the Purchaser. If Supplier supplies medicines beyond above limit, additional cost incurred on the quality testing shall be deducted from the Bills of the Supplier.

8.5 The Supplier supplying vaccines, serum and biological products shall mandatorily submit a quality assurance certificate from Government laboratory.

8.6 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found below standard in testing, the supplier shall have to replace the full stocks of Indent / ordered medicine, surgical items and chemicals quantity, with fresh standard quality medicine, surgical items and chemicals, within 60 days, even if some part of the drug from received stock has been consumed.

8.7 Besides this, the Purchaser will be free to take actions against the Supplier for any compensation.

8.8 The Supplier may be blacklisted and/or debarred, for a product purchased by indenter, is declared SUB STANDARD, for producing wrong documents, non supply of medicine, surgical items and chemicals under contract or any other errors. The duration of blacklist and/or debar shall be for 3 years.

8.9 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found of below standard in testing, in such case all the cost incurred in testing will be borne by the Supplier.

## 9. Payments

Payment for Medicine, surgical items and chemicals and Services shall be made as follows:

9.1 The Supplier's request(s) for payment shall be made to the Purchaser in writing, accompanied by an invoice in triplicate copies describing, as appropriate, the Medicine, surgical items and chemicals delivered and the Services performed, and upon fulfillment of other obligations stipulated in the contract.

9.2 In case the consignee is other than I/C Central Ware House Dehradun, then the invoice/bill, in triplicate should have receiving from the consignee(s), along with stock book page entry, duly verified, signed and stamped by consignee(s).

9.3 Ninety percent (90%) of the contract price shall be paid within one month of receipt of Invoice as described above of Medicine, surgical items and chemicals from the consignee (s)

9.4 The invoice shall be raised after complete supply of the Medicines, Surgical Items and Chemicals etc. as per the Purchase Order. Part payment will not be done for a Purchase Order.

9.5 From the supplied product the purchaser will collect samples of all batches on random basis and these samples shall be sent to the State government approved testing center Laboratories. After receiving the successful test results i.e. found of standard quality, the balance payment of 10% shall be released within 30 days.

9.6 After opening of each Bid and up to the Contract Period, any change in the tax rates shall be applicable as per the Government Orders.

9.7 Those manufacturer or supplier who does not have Depot/C&F in Uttarakhand, they can supply their product only after they enter into a contract with a local distributor, and will supply their product through such distributor. The bill will be accepted from distributor of Uttarakhand State only.

#### **10. Delays in Supplier's performance**

10.1 Delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of the Services shall be made by the Supplier in accordance with the time schedule specified by the Purchaser in the Schedule of Requirements/ purchase order.

10.2 If at any time during performance of the Contract, the Supplier or its sub-contractor(s) should encounter conditions impeding timely delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of Services, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing about the fact of the delay, it's likely duration and its cause(s). As soon as practicable after receipt of the Supplier's notice, the Purchaser shall evaluate the situation and may, at its discretion, extend the Supplier's time for performance with or without liquidated damages, but to a maximum of 21 days.

#### **11. Liquidated damages**

If the Supplier fails to deliver any or all of the Medicine, surgical items and chemicals or to perform the Services within the period(s) specified in the Contract, the Purchaser shall, without prejudice to its other remedies under the Contract, 0.5% per week shall be deducted of the cost of Medicine, surgical items and chemicals on unperformed Services which are not supplied/ performed as per the time schedule. Maximum deduction shall be 10 % of total cost of Contract amount and DG, Medical Health shall be intimated for, further actions which may be termination of the Contract and the Performance Security of the Bidder may be forfeited whole or proportionate.

#### **12. Force majeure**

(A) The Supplier shall not be liable to forfeit its performance security, liquidated damages or termination for default, if and to the extent that, it's delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure.

(B) For purposes of this Clause, "Force Majeure" means an event beyond the control of the Supplier and not involving the Supplier's fault or negligence and not foreseeable. Such events may include, but are not limited to, acts of the Purchaser either in its sovereign or contractual capacity, wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions and freight embargoes.

(C) If a Force Majeure situation arises, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Purchaser in writing, the Supplier shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event.

13. The supplying firms will Emboss/Print U.K.G Supply Not for Sale will be printed on each label of the Bottle/Vials/Strips/Boxes or Cartons etc. No supplies should be accepted if such embossing & Printing is not done on the supplies.
14. Every care has been taken to see that rates quoted and approved have been correctly notified in the Notification but in case of any discrepancy either in rates or in specification or any nature in other details, it will be the duty of the firm that they should intimate to the C.M.S.D. DG Medical Health under registered cover latest within a month so that necessary action may be taken.
15. The Firms while sending the bills will certify that the rates charged are applicable and have also been approved by the CMSD and in case of any default they are prepared to make adjustments.
16. The firms should also certify on the bills that the supplies are according to specification and the makes approved by the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand and are in accordance with the latest DRUG ACT.
17. The attention of the Indenting Officers is drawn to the various lists of items published by the firms. It has been found that in some cases the firms includes unapproved items in their lists of approved items. It is responsibility of the Indenting Officers to consult the Gazette Notification before placing the actual order and see that the order for only approved items is placed. Such cases of misrepresentation should immediately be brought to the notice of Director General of Medical Health & F.W. Uttarakhand (CMSD) Dehradun sending copy of the list printed, by the particular firms. In case any firm is found doing so, strict action will be taken against them and their names will be deleted from Rate Contract without any notice to them and in addition they may be debarred.
18. No Assistance will be provided for release of the raw material or procurement of import license.
19. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand CMSD Dehradun reserves the right to call Tender for Quantity Contract or parallel Rate contract and also to finalize them at any time during the period of the rate contract.
20. It will be condition of the contract that although during the currency of the contract the price approved in this rate Contract arrangement will remain firm but however in the event of prices going down the contractor will promptly furnish such information to enable this office to amend the contracted rates for supplies at Rate lower than the rate contract, the attention of the firm is drawn to it.
21. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun or his authorized representative may inspect the premises of the manufacturing units to assess and verify that the item quoted as own made are actually manufactured by them.

22. All supplies shall have to be made strictly confirming to approved specification in accordance with the latest drug Act and Drug Act 1940.
23. If, during the Contract period, the Firm under Contract supplies any Medicine(s), Surgical Item(s) or Chemical(s), to any individual, institution, organization, state or any department or organization of GoI and/or State at the rate lesser than the rate under Rate Contract, in such case the Firm shall immediately inform the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun and supply at the same reduced rate. The above stipulation will not however apply
  - a. Exports by the Contractor.
  - b. Sale of goods as original goods at a price lower than the price charged for normal replacement.
24. Supplies must be completed within three weeks (21 days) from the date of issue of the Purchase Order from the Indenting Officers. If the Firm does not supply within six weeks (42 days) time from the date of issue of the Purchase Order from indenting officer, a further period can be extended up to three weeks if the firm apply for such extension before the expiry of six weeks (42 days) time giving valid satisfactory reasons. In case of non supply, the names of such defaulting firms should be intimated to CMSD section of the Directorate by registered post so that the necessary action against the firm.
25. All supplies shall be made as per IP/ BP or USP/ BPC whenever this has been Omitted due to printing error wise it shall be or other as per IP and in its absence BP taken for all purpose that supplies are to make as per IP.
26. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun authorizes the Drug controller of the State his access him to prosecute and take suitable action against firms defaulting as per drug act or per terms of contract.
27. During the pendency of contract if the license is withdrawn or any other action is taken by Drug Controller or his agent etc. the contract shall automatically come to a close with the firm. Against whom the action is being taken, firms shall see that they have valid drug license for the products approved in their favour and which they may supply during its pendency else they themselves shall be responsible for the same.
28. In the event of the prices being gone down the contracting firm may please intimate the same to the Director General Medical of Health services Uttarakhand Dehradun immediately for issuing necessary corrigendum in this regards and they will also charge the reduced rates from the Indenting Officers of the State. In case such information is received from the contracting firm that they are selling items approved in their favour at reduce rates either in open market or anywhere else. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun reserves the right to cancel the items of entire contract finalized with them and to debar the firm from further tendering.
29. This contract shall exclusively be governed by the terms and conditions mentioned in this notification the relevant conditions mentioned in the tender notice CMSD, tender form and relevant conditions mentioned in the agreement form (sent to the firm along with acceptance letter separately )
30. The Indenting Officers are advised to report the damages /defects notice in supplies to suppliers for notification repair replacement as the case may be, within fifteen days of the receipt / of the material.

31. In case of any complaint against the supplier for delay in supplies or defective supplies etc. The Indenting Officers are advised to report the matter under registered post to the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun (CMSD) Section promptly for necessary action by registered post/e-mail.

### NOTIFICATION No. 03 [M]

Enclosure of Notification No. 15P/Store/22/2021/ 13434 Dated: 01 July, 2021

#### ANNEXURE 'A'

SN	Name of Firm	Phone No./Fax No. & E-mail
1	M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd. 128/5, Swiss House, Vishwas Nagar, Delhi-110032	Mr. Naresh Ramteke, 8470027121-23 & 9868217950 e-mail id: medipoldel@gmail.com
2	M/s Tirupati Medicare Ltd., Nahan Road, Ponta Sahib, Sirmour, Himachal Pradesh	Mr. Nitin Kumar, 8802137137 e-mail: nitin.kumar@tiripatigroup.co.in

### NOTIFICATION No. 03 [M]

#### ANNEXURE 'B'

Enclosure of Notification No. 15P/Store/22/2021/ 13434 Dated: 01 July, 2021

List of medicines/drugs approved in Rate Contract, validity period and description of Consignee

SN	Name of Medicine/vaccine etc.	Packing unit offered	Unit Cost per tab or per bottle (Rs.)	GST (Rs.)	RC Validity Period	Name of approved Firm	Consignee/State Drug Ware house or FOR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tab. Zinc Dispersible 10 mg	1x10 Strip	0.21	0.0252	01-07-2021 to 30-06-2023	M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	FOR
2	Syrup Dicyclomine 10 mg/5 ml	60 ml bottle	7.70	0.92	01-07-2021 to 30-06-2023	M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	FOR
3	Syrup Prednisolone 5 mg/5 ml	60 ml bottle	15.80	1.90	01-07-2021 to 30-06-2023	M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	FOR
4	Drops Vitamin D 400 IU/ml	15 ml	7.50	0.90	01-07-2021 to 30-06-2023	M/s Tirupati Medicare Ltd.	FOR

TRIPTI BAHUGUNA,  
Director General.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 31 हिन्दी गजट/268-भाग-1-क-2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।